भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2806
गुरुवार, 12 दिसंबर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों का निजीकरण

2806. श्री के. राधाकृष्णन:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से कितने विमानपत्तनों का निजीकरण किया गया है;

(ख) वर्तमान में विमानपत्तनों का संचालन करने वाली कंपनियों का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का आगामी पांच वर्षों में किन-किन विमानपत्तनों का निजीकरण करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन परिसम्पतति यों के निजीकरण पर सरकार का औचित्य क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने वर्ष 2014 से लखनऊ, अहमदाबाद, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में अपने छह हवाईअड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत बेहतर प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए लीज पर दिया है। वर्तमान में इन हवाईअड्डों का संचालन करने वाली कंपनियों का विवरण इस प्रकार है:

(1) चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ - मैसर्स लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल)

(2) सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद - मैसर्स अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एआईएएल)

(3) मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा - मैसर्स मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमएआईएएल)

(4) जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा - मैसर्स जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल)

(5) लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, गुवाहाटी - मैसर्स गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल)

(6) तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा - मैसर्स टीआरवी-केरल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएएल)

इन हवाईअड्डों का वास्तव में निजीकरण नहीं किया गया है, बल्कि 50 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर दिया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, लीज की अवधि के दौरान हवाईअड्डे की भूमि का स्वामी रहेगा और रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार लीज की अवधि समाप्त होने के पश्चात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि तथा अन्य परिसंपत्तियां वापस मिल जाएंगी।

(ग) : राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अनुसार, एएआई के 25 हवाईअड्डों अर्थात, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयंबटूर, नागपुर, पटना, मदुरै, सूरत, रांची, जोधपुर, चैन्ने, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इम्फाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंदरी को वर्ष 2022 से 2025 तक लीज पर देने के लिए चिह्नित किया गया है।

(घ) : एएआई के हवाईअड्डों को उनके बेहतर प्रबंधन, निजी क्षेत्र की दक्षता और निवेश का उपयोग करने के लिए लीज पर दिया जाता है। हवाईअड्डे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरे हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था पर इनका गुणक प्रभाव होता है। पीपीपी के तहत लीज पर दिए गए हवाईअड्डों का प्रचालन, प्रबंधन और विकास करने वाले निजी भागीदार द्वारा बनाए गए उन्नत हवाईअड्डे की अवसंरचना और सुविधाओं का अंतिम लाभार्थी राज्य और यात्री होते हैं। लीज पर दिए गए हवाईअड्डों से एएआई को मिलने वाले राजस्व का उपयोग देशभर में हवाईअड्डा अवसंरचना के विकास के लिए भी किया जाता है।

*****